



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 7 जून, 2004/17 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

जिमना-171 009, 21 मई, 2004

संख्या 1-58/69-फिन(एल0 ए0)पार्ट 4.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-58/69-फिन (एल0 ए0) पार्ट-4, तारीख 30 जुलाई, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-3 (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-3 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-“अ” का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वर्ग-3 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 से संलग्न उपाबन्ध-“अ” में :—

(क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“73. (तिहतर)”

(ख) स्तम्भ संख्या-3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“वर्ग-3 (अराजपत्रित) लिपिकिय सेवाएं”

(ग) स्तम्भ संख्या-6 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“18 से 45 वर्ष”

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“सामान्य लिपिकिय काडर के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनकी कम से कम 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।”

टिप्पण. (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इरा शर्त हो, अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा जो निर्यातित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) को शामिल करके के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रक्खे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उसमें कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्थगिकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मेड फोर्स परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रुलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत बरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रुलज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत बरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होना इसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अग्रगणित रहेगी।

(क) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है”

आदेश द्वारा,

एम० एम० परमार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin (LA) Part-4, dated 21st May, 2004 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 21st May, 2004

No. 1-58/69-Fin(LA)Part-4.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified *vide* this department No. 1-58/69-Fin(LA)Part-4, dated 30-7-1997, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called Himachal Pradesh Local audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2004.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure “A”.*—In Annexure “A” appended to the Himachal Pradesh Local Audit Department, Junior Auditor, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(a) For existing provision against Column No. 2, the following shall be substituted, namely:—

“73 (Seventy three)”

(b) For existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:—

“Class-III (Non Gazetted) Ministerial Services”

(c) For existing provisions against Column No. 6, the following shall be substituted, namely:—

“18 to 45 years”

- (d) For existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

“By promotion from amongst the incumbents of the Common Clerical cadre with ten years regular service or regular combined with *ad hoc* service.”

Note.—In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, Provided that;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including the service rendered on *ad hoc* basis, in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered shall remain unchanged; and

- (e) For the existing provisions against Column No. 14, the following shall be substituted, namely:—

“A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India”

By order,

S. S. PARMAR,
Additional Chief Secretary (Finance).